बजट को देखकर लगता है हमारा क्या है, सब कुछ तो ठाकुर का है : हरीश चौधरी

बीजेपी विधायकों ने हरीश चौधरी पर जातिवाद फैलाने और एक वर्ग को आहत करने का आरोप लगाया

- संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा हम सब एक हैं, आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए
- विधायक अमृतलाल मीणा ने कहा हरीश चौधरी एससी-एसटी को ठाकुर बता रहे थे। वो कितने सच्चे, कितने काले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मीणा ने कहा कि देश की पाइपलाइन, पूरी रिफाइनरी खा गए

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बजट की तुलना ठाकुर का कुआं कविता से की। हरीश चौधरी ने कहा क्रांतिकारी कवि ओमप्रकाश वाल्मीकि ने ठाकुर का कुआं कविता के जरिए भेदभाव का दर्द बयां किया था। वो ही दर्द इस बजट को पढ़कर दिखेगा।

उन्होंने कहा कि मैं कम पढ़ा जरूर हूं, केवल पोस्ट ग्रेजुएट हूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का खेत-खलिहान ठाकुर के। हमारा क्या है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ ठाकुर का है। हम आरक्षण के नाम पर दर्द बयां करते हैं तो हंसी उड़ाई जाती है। 80 फीसदी संसाधन ऊंची जातियों के पास हैं। हम पिछड़ों के पास क्या है। हम लोग जो ओबीसी में पिछड़े आते हैं उनका क्या है। केवल 17 परसेंट मिला। नौकरियों में रोस्टर के नाम पर खेल किया जाता है। ओबीसी वोट के समय ही याद आते हैं।

बीजेपी विधायकों ने हरीश चौधरी पर जातिवाद फैलाने और एक वर्ग को आहत करने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सभापति से इसे कार्यवाही से निकालने की मांग की। पटेल ने कहा हम सब एक हैं, आहत करने वाली टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पटेल ने हरीश चौधरी से कहा कि आपने जो बोला आपके विषय के अनुकूल नहीं है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस पर सभापति संदीप शर्मा ने कहा कि जो सदन के अनुकूल नहीं होगा उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा ने हरीश चौधरी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा हरीश चौधरी एससी-एसटी को ठाकुर बता रहे थे। वो कितने सच्चे, कितने काले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मीणा ने कहा कि देश की पाइपलाइन, पूरी रिफाइनरी खा गए। उस एरिया में जाकर देखें, किसी पर उंगली उठाने से क्या होता है। सब जानते हैं पूरे बाड़मेर को लूट लिया। आदिवासी को ठाकुर कह रहे हैं। यह सहन नहीं होगा, नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा एससी-एसटी।

इस पर हरीश चौधरी ने कहा हिम्मत है तो कर लो, यह आवाज मजदूर पिछड़ों की है, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं यह दबा नहीं सकते हैं। हरीश चौधरी जर खरीद लोगों के आगे नहीं झुकेगा।

'प्रदेश में 7 अगस्त को 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे'

अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने गुरूवार को सभी जिलों के कलेक्टरों को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए।

- इस अभियान में वन विभाग 60 लाख और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 40 लाख पौधे लगाएगा

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार ने गुरूवार को कहा कि प्रदेश में ''हरियालो राजस्थान'' अभियान के तहत 7 अगस्त हरियाली तीज के शुभ अवसर पर प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्व में ही आवश्यक तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि समय रहते पौधों के लिए गड्ढे खोदे जाए। साथ ही यदि किसी जिले में पौधों की उपलब्धता नहीं है तो पूर्व में ही सूचित करें ताकि समय रहते उपलब्ध कराए जा सकें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस महत्वाकांक्षी पहल को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश को हरियाली से भरने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान में हमारा लक्ष्य न केवल अधिक से अधिक पौधे लगाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे पौधे जीवित रहें और फल-फूल सकें। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में इस अभियान को सफलता पूर्वक लागू करे और इसकी निगरानी करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिसमें महिला जनप्रतिनिधि, महिला अधिकारी/कर्मचारी, लखपति दीदी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका, आशा सहयोगिनी, राजीविका सखी, नरेगा महिला मेट, महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, स्कूल एवं कॉलेज की छात्राएं आदि हर स्तर के कार्यक्रम में भागीदारी हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अभियान में महिलाओं को जोड़ा जाए। साथ ही जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजीविका की महिलाएं इस कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग ले, यह सुनिश्चित किया जाए। ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग ले और प्रदेश को हरा-भरा बनाने में अपना योगदान दे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी ने कहा कि वन विभाग द्वारा 7 अगस्त से वृक्षारोपण के दौरान लगने वाले पौधे वन भूमि में ही लगाए जाऐंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि इस दिन बड़े स्तर पर वृक्षारोपण होना है। अतः श्रमिकों की समस्या नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। शासन सचिव, पंचायती राज रवि जैन ने कहा कि पौधों के वृक्षारोपण के बाद उन्हें फोटो सहित राज जिओ ट्री एप पर अपलोड करें। इस महत्वपूर्ण अभियान में ग्रामीण एवं पंचायती राज, राजीविका, जलग्रहण विकास, शिक्षा, कृषि एवं उद्यानिकी, वन एवं पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, एनएएचआई, उद्योग, रीको, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, जल संसाधन, चिकित्सा, खनिज, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन सहित अन्य विभागों की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी में एविएशन सिक्युरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लोगों का अनावरण

- डीजी इंटेलिजेंस अग्रवाल ने आईबी में कांस्टेबल के पहले बैच से संवाद किया

जयपुर। पुलिस महानिदेशक इन्टेलीजेंस, राजस्थान संजय अग्रवाल ने इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर में राज्य विशेष शाखा के प्रथम बार चयनित कांस्टेबल के बैच से संवाद किया। अग्रवाल ने इस मौके पर एविएशन सिक्यूरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयपुर के लोगो का भी अनावरण किया।

डीजी अग्रवाल ने आईबी के प्रथम बैच के कांस्टेबल प्रशिक्षुओं से संवाद कर सभी प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान में तकनीकी विकास के परिदृश्य में आसूचना एवं सुरक्षा की दृष्टि से मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का संदेश दिया।

कार्यक्रम के अन्त में अकादमी निदेशक दीपक भार्गव ने प्रशिक्षण के दौरान भविष्य की चुनौतियों के अनुसार किये जा रहे नवाचारों के अन्तर्गत सोशल मीडिया निगरानी, साईबर सुरक्षा एवं ड्रोन प्रशिक्षण के संबंध में अवगत कराया। साथ ही संस्था में चल रहे नवीनीकरण कार्यों की जानकारी दी।

समारोह के दौरान अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालीनी सक्सेना को डीजी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) द्वारा प्रदत्त डीजी डिस्क प्रदान की। एएसटीआई के इन्स्ट्रेक्टर हीरालाल शर्मा, सुमिता शर्मा, राजकुमार शर्मा, विकास टिबरेवाल को बीसीएएस इन्स्ट्रेक्टर चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। साथ ही उप निरीक्षक रामचन्द्र कुमावत को स्क्रीनर चिन्ह एवं प्रमाण पत्र तथा एएसटीआई की स्थापना में उत्कृष्ट कार्य करने पर रमेश शर्मा को प्रमाण पत्र मय चिन्ह प्रदान किया गया।

इस अवसर पर महानिरीक्षक पुलिस सुरक्षा राजेश मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस एसएसबी विकास शर्मा, उप महानिरीक्षक पुलिस इन्टेलीजेंस डॉ. राजीव पचार, उप महानिरीक्षक पुलिस एवं निदेशक, इन्टेलीजेंस प्रशिक्षण अकादमी जयपुर के प्रशिक्षणार्थी एवं स्टाफ उपस्थित रहा।

दिलावर ने सदन में माफी मांगी

जयपुर, (वि.सं.)। आदिवासियों के डीएनए वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में आज माफी मांग ली है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही दिलावर को स्पीकर ने बोलने की इजाजत दी। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। इसके बाद दिलावर ने कहा कि यदि विपक्षा को या मेरे आदिवासी भाईयों को मेरे बात करने से, मेरे बोलने से या कुछ बातों से कष्ट हुआ है तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करता हूं। गौरतलब है कि विपक्षी कांग्रेस और बीएपी ने मदन दिलावर का सदन में बहिष्कार कर रखा था। दिलावर जैसे ही सदन में शिक्षा से जुड़े सवालों या किसी मुद्दे का जवाब देने खड़े होते थे, विपक्ष हंगामा करता था।

जैसलमेर में हुए गौशालाओं के फर्जीवाड़े में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के शामिल होने का आरोप

पिछली सरकार के समय दो साल में 51 करोड़ 23 लाख रुपये का अनुदान उठा लिया गया : कालीचरण सराफ

जयपुर, (वि.सं.)। जैसलमेर जिले की गौशालाओं में कांग्रेस राज के दौरान हुए फर्जीवाड़े में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और उनके नजदीकी लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया।

सराफ ने कहा कि जिन 12 गौशालाओं का अनुदान रोका गया वे पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और उनके नजदीकी लोगों की गौशालाएं थीं। उन्होंने गड़बड़ी की, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण उनकी जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन गौशालाओं में 7129 गायें बताई गई और जांच के दौरान केवल 310 मिलीं। आपने अनुदान तो रोक दिया पर क्या यह सही है कि पिछली सरकार के समय दो साल में 51 करोड़ 23 लाख रुपये का अनुदान उठा लिया गया। उस पर क्या वसूली की कार्यवाही करेंगे। जवाब में पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इस मामले की एसीबी में जांच प्रक्रियाधीन है। 32 गौशालाओं ने फर्जी तरीके से अनुदान उठाया, वहां जांच करवाने पर पाया गया कि जितनी गायों की संख्या बताई थी, उतनी गायें जांच में मौके पर नहीं मिलीं। अनुदान में फर्जीवाड़ा हुआ तो वसूली भी करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी पहुंच वाला आदमी हो, यदि जांच में फर्जीवाड़ा पाया गया तो कार्यवाही करेंगे और वसूली भी करेंगे।

35 किलो मांस जब्त, दुकान सीज

जयपुर । नगर निगम हैरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने गुरुवार को बिना लाइसेंस और खुले में मीट बेचने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक दुकान सीज की है। हेरिटेज निगम के पशु प्रबंधन शाखा उपायुक्त राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि हेरिटेज निगम की ओर से बिना लाइसेंस और खुले में मांस बेचने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को निगम टीम ने पठानों का चोक, ब्रह्मपुरी, हांडीपुरा, घोड़ा निकास रोड, कसाइयों की मोरी, चार दरवाजा इलाके में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर खुले में मीट बेचा जा रहा था । जिस पर कार्रवाई करते हुए 7300रुपए का चालान किया गया।

'सामाजिक न्याय-अधिकारिता विभाग का बजट इस बार 30 प्रतिशत बढ़ाया'

- मंत्री अविनाश गहलोत ने सदन में कहा, ''भजनलाल सरकार ने पेंशन में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा दी''

जयपुर (विसं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने महंगाई के बावजूद आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बजट को बढ़ाकर विकसित राजस्थान-2047 का स्वरूप दिया है। सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। आमजन को राहत देने के लिए 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर उसे समयबद्ध रूप से क्रियान्वित भी किया।

अविनाश गहलोत गुरुवार को विधानसभा में मांग संख्या -31 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 1 खरब 18 अरब 72 करोड़ 89 लाख 37 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विकास और सशक्तीकरण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड्स को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार, बालिकाओं को सम्बल तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए पहली बार 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री गहलोत ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान व उन्हें राहत प्रदान करने के लिए अनुजा निगम एवं अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम आदि के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

भील प्रदेश हमारा अधिकार : थावरचंद

जयपुर, (वि.सं.)। बीएपी विधायक थावरचंद गहलोत भील प्रदेश लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में पहुंचे। उन्होंने विधानसभा में भील प्रदेश की मांग उठाई। थावरचंद ने कहा कि आज जब मैं सदन में बोल रहा हूं उस समय मानगढ़ धाम में 4 राज्यों के 10 लाख आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और राजस्थान में बांट दिया गया है।

पुलिस की सक्रियता के चलते फायरिंग की घटनाओं में आई कमी : दिनेश एम.एन.

जयपुर। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस एजीटीएफ एवं अपराध दिनेश एमएन ने कहा कि पराधियों की धर पकड़ एवं इनकी गतिविधियों पर निगरानी के सकारात्मक परिणाम स्वरूप प्रदेश में फायरिंग की घटनाओं में इस साल बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि फायरिंग के प्रकरणों में वर्ष 2023 के मुकाबले इस वर्ष जून महीने तक दर्ज किए गए प्रकरणों की संख्या में 41.89 प्रतिशत, घायलों की संख्या में 59.56 एवं मृतकों की संख्या में 44.44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। एमएन ने बताया कि प्रदेश में फायरिंग के मामले में साल 2021 में जून महीने तक 223 प्रकरण दर्ज हुए। जिसमें 129 घायल व 32 की मौत हो गई। साल 2022 में जून महीने तक 272 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 151 घायल व 30 की मौत हो गई।

इसी प्रकार साल 2023 में जून महीने तक 265 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें 183 घायल व 27 की मौत हो गई। इसकी तुलना में साल 2024 में जून महीने तक 154 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमे 74 घायल व 15 की मौत हुई है।

एन्टी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 16 दिसम्बर2023 से अब तक 37 ईनामी अपराधी गिरफ्तार किये गये। इनमें 1 लाख का 1, 50 हजार के 6, 35 हजार के 3, 25 हजार के 11, 20 हजार के 2, 15 हजार का 1, 10 हजार के 5 और 5 हजार के 8 ईनामी शामिल है। इनमें 25 हजार का ईनामी आतंकवादी मेराजूद्दीन को गिरफ्तार किया था।

वहीं अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही में कुल 14 अपराधी गिरफ्तार कर 8,628 किलोग्राम डोडा चुरा व पोस्त, 2 किलो 50 ग्राम अफीम 534 कार्टून अवैध अग्रेजी शराब एवं 124 कार्टून अवैध देशी शराब जब्त की गई।

अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्रवाई में कुल 17 अपराधी गिरफ्तार कर 68 अवैध हथियार, 19 मैग्जीन व 112 कारतूस जब्त किए गए।

राजू ठेहट गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले अपराधी को करौली से 9 अवैध देशी पिस्टल, 16 मैगजीन व 02 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

डकैतों व बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले अपराधियों को धौलपुर से 20 अवैध हथियार व 32 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

कई आदिवासी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए : समाराम

विधायक समाराम ने सदन में कहा कि, ''जिन्होंने धर्म बदल लिया, उनको जनजाति सूची से हटाना चाहिए, क्योंकि ये अपना धर्म तो ईसाई बताते हैं और आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं का फायदा उठाते हैं।''

- विधायक गणेश घोघरा ने आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग बताते हुए भिन्न कोड तय करने और आदिवासियों को आठ लीटर मुहएं रखने की अनुमति देने की मांग उठाई

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । विधायक समाराम ने गुरूवार को विधानसभा में टी.ए.डी. और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कहा कि, मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। यहां कई आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उनको जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपना धर्म तो ईसाई बताते हैं और आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं का फायदा लेते हैं। जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते है, उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए।

विधायक समाराम ने कहा कि हर आदिवासी हिंदू है, क्योंकि हिंदू वहीं है, जो सनातन से चला आ रहा है। आदिवासी भी सनातनी है। ऐसे लोगों को जनजाति की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, जो खुद को हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि जनजाति का आरक्षण केवल हिंदुओं को ही दिया गया है। समाराम से पहले किशनगंज से भाजपा विधायक ललित मीणा ने भी सदन कहा था कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने विधानसभा में कहा कि, रोस्टर में एससी-एसटी के पद घटाए जा र रहे हैं। पद कम नहीं होने चाहिए। उन्होंने बिजली के कनेक्शनों में एससी-एसटी को प्राथमिकता देने, हर जिले में वृद्धा आश्रम बनाने, नशा मुक्ति केन्द्र खोलने की मांग करते हुए चित्तौडगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संयुक्त निदेशक स्तर का का अधिकारी लगाने की आवश्यकता जताई।

डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा ने सदन में आदिवासियों के लिए अलग से कोड लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा- जब देश में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिन्दू और मुस्लिम धर्म का कोड अलग है तो फिर आदिवासियों का कोड अलग क्यों नहीं हो सकता है। गणेश घोघरा ने आदिवासी कोड की मांग करके एक बार फिर आदिवासियों को हिन्दू धर्म से अलग बता दिया है। इसके साथ ही घोघरा ने जातिगत जनगणना की मांग भी की है। उन्होंने कहा- देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसी से पता चलेगा कि देश में कितने आदिवासी हैं, उसी के अनुसार हमें आरक्षण मिलना चाहिए।

घोघरा ने कहा कि आदिवासियों की परम्परा में ही वार-त्यौहार (महुएं देशी शराब का रूप) का चलन है। एकाध लीटर सभी आदिबासी घरों में रखते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ती है और मामले दर्ज हो जाते हैं। सरकार टीएसपी एरिया में आठ लीटर महुएं को रखने की परमिशन दें और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तो शहरों की बार-शराब की दुकानों को भी बंद कर दे।

उन्होंने माही डेम का पानी सबसे पहले बांसवाड़ा में पेयजल के लिए देने, जनसंख्या के आधार पर टीएसपी में आरक्षण, प्रशासनिक भर्ती में छह फीसदी आरक्षण, जातिगत जनगणना कराने, आदिवासियों के लिए हिन्दू, मुस्लिम, जैन इत्यादि की तरह अलग से कोड बनाने, एरिया में उद्योग धंधे विकसित करने, मनरेगा में मजदूरी दिवस दो सौ दिन करने की मांग की।

रानीवाड़ा से कांग्रेस के विधायक रतन देवासी ने चर्चा के दौरान कहा कि सिरोही से सटे जालौर इलाके में 40 फीसदी एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहां टीएसपी एरिया नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे इसके लिए प्रयास करें और तब तक उन्हें टीएसपी एरिया में चल रही योजनाओं का फायदा दें।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिए जाने वाले दो लाख रूपए के रोजगार लोन पर मार्जिन मनी का प्रावधान हटाने, विशेष योग्यजन को स्कूटी की जगह रोजगार के लिए ई-रिक्शा देने का प्रावधान करने, टीएसपी एरिया में एसटी वर्ग को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता देने, जयपुर में कोचिंग छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाने, आवासीय छात्रावास के साथ स्कूल के अलावा कॉलेज भी बनवाने की मांग भी की है।

'भारत सरकार से बजट में सहकारी बैंकों के लिए पूंजीकरण सहायता की मांग'

जयपुर (कासं)। ऑल इण्डिया को-ऑपरेटिव बैंक एम्पलाईज फैडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चेन्नई में संपन्न हुई। बैठक में भाग लेकर आए फैडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु से जी वाईरप्पन ने की। एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सीएच वेंकटचलम ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन दिया । आमेरा ने भी मुद्दों पर बैठक को संबोधित किया ।

सहकार नेता आमेरा ने बताया कि बैठक में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था व सहकारी साख आंदोलन को सक्षम , सुदृढ़ व पारदर्शी बनाए जाने पर विचार करते हुए देश के किसानों के हित में सहकारी बैंकों के पूँजीगत संसाधन के लिए भारत सरकार से सहकारी बैंको के लिए बजट में पुनर्पूंजीकरण सहायता का बजट प्रावधान करते हुए सहायता जारी करने की माँग की गई। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष व्यावसायिक बैंको के लिए करोड़ों रूपये की पूँजीगत सहायता जारी की जाती है लेकिन किसानों व कृषि से जुड़े सहकारी बैंकों को कोई पूँजीगत सहायता नहीं दी जा रही है जबकि सहकारी बैंकों से करोड़ों रुपये का आयकर उगाया जाता है, जिससे सहकारी बैंक कमजोर हो रहे है।

आमेरा ने बताया कि बैठक में भूमी विकास बैंकों का सविलयन व समामेलन में पीएलडीबी को एसएलडीबी की शाखा बनाकर इस सेक्टर को पूँजीगत सहायता से आर्थिक पुनरुद्धार करना, सहकारी बैंकिंग में सीसीबी को अपैक्स बैंक की शाखाए बनाकर टू टियर बैंकिंग व्यवस्था से राज्य में एक बड़ा सहकारी बैंक बनाना, पेक्स कार्मिक के सेवा शर्तों में वेतन भुगतान सुनिश्चित करना , सहकारी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन सुविधा लागू करना, ईपीएस 95 से देय उच्च पेंशन जारी करना , सहकारी बैंकों पर आयकर प्रावधान समाप्त कर पहले की तरह आयकर फ्री करना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान व रिजर्व बैंक के निर्देश प्रभावी रूप से लागू करना, नेट व डिजिटल बैंकिंग स्वीकृति के लिए उदारता बरतना सहित अरबन बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे ग़बन व घोटालो से आमजन को सुरक्षित करना आदि मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गये।

आमेरा ने बताया कि फ़ैडरेशन के अखिल भारतीय आव्हान पर इन सभी मुद्दों व माँग को लेकर अगस्त-सितंबर माह में सहकारी बैंक कर्मचारी व अधिकारी राज्यों में सेमिनार व सम्मेलन आयोजित कर कार्मिको को जागरूक अभियान चलायेंगे।

बिजली-पानी के मुद्दे पर सदन में हंगामा

जयपुर, (वि.सं.)। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान बिजली संकट के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से बिजली संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज बिजली को लेकर त्राहिमाम है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई बिजली,पानी मांगने आंदोलन करता है तो सरकार जेल में डाल देती है। बूंदी में हमने प्रदर्शन किया तो हमारे नेताओं के खिलाफ ही मुकदमे कर दिए।

इसके बाद उर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जवाब में कहा कि कांग्रेस सरकार ने दूसरे राज्यों से समझौते किए और पीक सीजन में जब राजस्थान में डिमांड ज्यादा होती है बिजली बैंकिंग समझौते के तहत उन राज्यों को वापस लौटानी पड़ती है।